नईदुनिया

भोपाल, 3 नवंबर 2026

निफ्टी में 388 अंकों की बढ़त, रिलायंस का शेयर 12 प्रतिशत चढ़कर 1,300 रुपये पर पहुंचा

शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 1,233 अंक उछलकर 75,693 पर बंद

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,233 अंकों की बढ़त के साथ 75,693 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 388 अंक चढ़कर 23,440 पर पहुंच गया। बाजार में तेजी की प्रमुख वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आई बड़ी उछाल रही। कंपनी का शेयर 12 प्रतिशत चढ़कर 1,300 रुपये पर पहुंच गया। इससे रिलायंस का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 17.59 लाख करोड़ रुपये हो गया।

बाजार में तेजी के पीछे तीन प्रमुख कारण रहे। पहला, विदेशी और घरेलू निवेशकों की खरीदारी। लंबे समय से बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशकों ने बुधवार को 871.83 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू निवेशकों ने भी 643.35 करोड़ रुपये का निवेश किया। बीते सात दिनों में विदेशी निवेशकों ने कुल 7,767 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। हालांकि,



बीते 30 दिनों में उनकी कुल बिकवाली 35,678 करोड़ रुपये रही।

दूसरा कारण बड़ी कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे रहे। सितंबर तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 34 प्रतिशत बढ़कर 29,550 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसके चलते कंपनी के शेयर में तेजी आई। टाटा स्टील, एनटीपीसी, मारुति और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

तीसरा कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रहा। ब्रेंट कच्चे तेल का भाव करीब तीन प्रतिशत गिरकर 110 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए कीमतों में गिरावट को बाजार के लिए सकारात्मक माना गया।

एशियाई बाजारों में सोमवार को मिला-जुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.24 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 0.42 प्रतिशत चढ़ा, जबकि जापान का निक्केई 0.33 प्रतिशत गिरा। इससे पहले 30 अक्टूबर को अमेरिकी बाजारों में गिरावट दर्ज की गई थी। डाउ जोन्स 1.09 प्रतिशत, नैस्डैक 2.86 प्रतिशत और एसएंडपी 500 सूचकांक 1.82 प्रतिशत नीचे बंद हुए।

त्यौहारी सीजन में अर्थव्यवस्था मजबूत, जीएसटी 2.31 लाख करोड़



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः महँगाई, ऊंची ब्याज दरों और वैश्विक तनाव के बावजूद देश में अक्टूबर के दौरान खरीदारी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई। त्योहारी सीजन में बाजारों की रौनक का असर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, वाहनों की बिक्री, डिजिटल भुगतान और बिजली की खपत के आंकड़ों में दिखाई दिया। इन क्षेत्रों में दर्ज बढ़ोतरी से अक्टूबर में मजबूत मांग के संकेत मिले हैं।

अक्टूबर में देश का जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वर्ष अक्टूबर में यह लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपये था। संग्रह में हुई बढ़ोतरी को त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में बेहतर खरीदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वाहन बाजार में भी रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई। अक्टूबर में देशभर में 5.25 लाख से 5.30 लाख कारें बिकीं। यह किसी एक महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री है। पिछले वर्ष अक्टूबर में लगभग 4.65 लाख कारों की बिक्री हुई थी। इस बार कारों की बिक्री में 13 से 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री भी नए स्तर पर पहुंच गई। अक्टूबर में 2.24 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके। वाहन पोर्टल के अनुसार, यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है।

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से 25.47 अरब लेनदेन हुए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। इन लेनदेन के जरिए कुल 31.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जिसमें सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पहली बार यूपीआई के माध्यम से प्रतिदिन औसतन एक लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।

अक्टूबर में देश की बिजली खपत भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 22 प्रतिशत बढ़कर 160 अरब इकाई हो गई। वहीं, डीजल की बिक्री में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इन आंकड़ों से त्योहारी महीने में खरीदारी, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत मिलता है।

खास-खबरें

कैट ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा, प्रदर्शन स्थल शहर से बाहर किया जाए

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सोमवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक आयोजनों के लिए शहर के बाहरी इलाकों में अलग से नियत स्थल अधिसूचित करने की मांग की है। कारोबार संगठन का कहना है कि दिल्ली में औसतन प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपये का व्यापार होता है। पिछले एक महीने में लगभग 14 दिन दिल्ली का सामान्य व्यापार प्रभावित हुआ है। दिल्ली देश का एक प्रमुख व्यापारिक एवं वितरण केंद्र है, जहां प्रतिदिन देश के विभिन्न राज्यों से लाखों व्यापारी खरीदारी करने और व्यापारिक गतिविधियों के लिए आते हैं। पिछले एक महीने से अधिक समय से बने अशांत माहौल, धरने-प्रदर्शनों और यातायात संबंधी व्यवधानों के कारण बड़ी संख्या में व्यापारी दिल्ली नहीं पहुंच सके। इसका सीधा असर थोक बाजारों, खुदरा व्यापार, छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों, परिवहन, होटल एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ा है।

अर्थव्यवस्था के बुनियादी स्तंभ मजबूत, आर्थिक वृद्धि के बारे में पूरे विश्वास से करें बातः वित्त मंत्री

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नागरिकों और व्यापारिक नेताओं से देश की आर्थिक वृद्धि के बारे में पूरे विश्वास और आशावाद के साथ बात करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी स्तंभों के कमजोर पड़ने के कोई संकेत नहीं हैं। मुंबई के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचीं सीतारमण ने एचएसबीसी के एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पूरी तरह मजबूत है और इसके बुनियादी स्तंभों में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या नाजुकता नहीं है।

वित्त मंत्री ने देश के नागरिकों, कॉर्पोरेट लीडर्स और विचारकों से अपील की कि वे देश की आर्थिक समृद्धि और वृद्धि के बारे में पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ बात करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी आर्थिक स्तंभ बेहद मजबूत हैं और इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। सीतारमण ने कहा कि सरकार के वित्तीय समावेशन एजेंडे में 'सभी के लिए बीमा' एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। केंद्र विशेष रूप से समाज के सबसे गरीब वर्गों के बीच बीमा और पेंशन योजनाओं तक पहुंच बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सरकार ऋण तक व्यापक पहुंच को भी प्राथमिकता दे रही है और उद्योग की आवश्यकताओं और युवाओं के कौशल के बीच अंतर को पाटने के लिए हर जिले में एआई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला वेदांत पॉली फैब्स का आईपीओ, 9 नवंबर को हो सकती है लिस्टिंग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः फ्लैक्सिबल पैकेजिंग मैटेरियल्स का निर्माण करने और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को 3-लेयर तथा 5-लेयर एलडी फिल्म्स, श्रिंक फिल्म्स, बैरियर फिल्म्स, प्रिंटेड लैमिनेट्स सहित मिल्क एवं ऑयल पाउच की आपूर्ति करने वाली कंपनी वेदांत पॉली फैब्स लिमिटेड का 56.68 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। कंपनी मुख्य रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) मॉडल पर काम करती है। लॉन्चिंग के बाद दोपहर 11:30 बजे तक इस आईपीओ को 18 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के इस आईपीओ में निवेशक 4 नवंबर तक बोली लगा सकते हैं। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 5 नवंबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 6 नवंबर को अलॉटेड शेयर सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी दिन जिन निवेशकों को शेयर का अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कंपनी के शेयर 9 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में बोली लगाने के लिए 88 से लेकर 94 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते का असर, एस्टन मार्टिन की कारें 4 करोड़ रुपये तक सस्ती

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का असर लग्जरी कार बाजार में दिखाई देने लगा है। ब्रिटेन की लग्जरी कार निर्माता कंपनी एस्टन मार्टिन ने भारत में अपनी सात कारों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। कंपनी के विभिन्न मॉडलों के दाम 1.84 करोड़ रुपये से लेकर 4.02 करोड़ रुपये तक घटाए गए हैं। कीमतों में यह बदलाव आयात शुल्क में मिली राहत के बाद किया गया है। कंपनी की सबसे महंगी कार वैंक्विश वोलांटे की कीमत में सबसे बड़ी कटौती हुई है। पहले यह कार 10.92 करोड़ रुपये में उपलब्ध थी, जबकि अब इसकी कीमत 6.90 करोड़ रुपये रह गई है। इस तरह ग्राहकों को 4.02 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। वैंक्विश कूपे की कीमत भी 10.11 करोड़ रुपये से घटाकर 6.40 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसमें 3.71 करोड़ रुपये की कमी आई है। डीबी12 एस श्रेणी की कारों के दाम भी घटाए गए हैं। डीबी12 एस कूपे की कीमत पहले 6.62 करोड़ रुपये थी, जो अब 4.10 करोड़ रुपये हो गई है। इस मॉडल पर 2.52 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। डीबी12 एस वोलांटे की कीमत सात करोड़ रुपये से घटाकर 4.35 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसमें 2.65 करोड़ रुपये की कमी आई है। कंपनी की लग्जरी खेल उपयोगी वाहन डीबीएक्स एस की कीमत 6.80 करोड़ रुपये से घटकर 4.15 करोड़ रुपये रह गई है। इसके दाम में 2.65 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। वैंटेज एस कूपे की कीमत 4.99 करोड़ रुपये से घटाकर 3.15 करोड़ रुपये कर दी गई है। वहीं वैंटेज एस रोडस्टर अब 3.35 करोड़ रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत 5.26 करोड़ रुपये थी। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन में निर्मित और पूरी तरह तैयार होकर भारत आने वाली पात्र कारों पर आयात शुल्क में राहत दी गई है। एस्टन मार्टिन ने इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाते हुए अपनी कारों की नई कीमतें घोषित की हैं।

- **कंपनी ने सात मॉडलों की कीमतें घटाईं**
- **वैंक्विश वोलांटे पर सबसे अधिक 4.02 करोड़ रुपये की कटौती**

भारत-यूरोपीय संघ के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर मंथन, बाजार में पहुंच बढ़ाने पर जोर

- **ब्रुसेल्स में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की उच्च स्तरीय बैठकें**
- **व्यापार सुगमीकरण, हरित प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग पर चर्चा**



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इन बैठकों में व्यापार सुगमीकरण, बाजार पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

वाणिज्य सचिव ने यूरोपीय आयोग के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा महानिदेशालय की महानिदेशक दित्ते जुएल जोर्जेसन के साथ बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए नए अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार किया। दोनों पक्षों ने निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही शेष प्रक्रियात्मक और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी महानिदेशालय के महानिदेशक कोएन डोएन्स के साथ बैठक में भारत-यूरोपीय संघ विकास सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श हुआ। इसमें सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

कराधान एवं सीमा शुल्क संघ महानिदेशालय के महानिदेशक गेरासिमोस थॉमस के साथ बैठक में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमीकरण और मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण बताया, जिससे व्यापार की लागत घटाने और वैध व्यापार की आवाजाही सुगम बनाने में सहायता मिलेगी।

वाणिज्य सचिव ने एंटवर्प के हीरा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इसमें वैश्विक हीरा मूल्य श्रृंखला, प्रमाणीकरण, जिम्मेदार स्रोत और भारत के बढ़ते हीरा विनिर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। भारत और बेल्जियम ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। एंटवर्प, मुंबई और सूरत प्रमुख हीरा केंद्रों के रूप में पहचाने गए।

इसके अतिरिक्त, बिजनेसयूरोप की गोलमेज बैठक में व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने तथा बाजार पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई। राजेश अग्रवाल ने भारत की आर्थिक वृद्धि, सुधारों और निवेश अवसरों को रेखांकित करते हुए यूरोपीय व्यवसायों को भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया।

मोबाइल में आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए चार्जिंग में बरतें सावधानी

नईदुनिया ब्यूरो, ग्वालियरः शहर के एक क्लिनिक में मोबाइल फोन अचानक फटने और उसमें आग लगने की घटना से अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय वहां मरीज और उनके परिजन मौजूद थे। मोबाइल में आग लगते ही लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। क्लिनिक कर्मचारियों ने तत्काल आग बुझाई। राहत की बात रही कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस घटना ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल और उसकी बैटरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मोबाइल में आग लगने या बैटरी फटने की घटनाओं के पीछे बैटरी में खराबी, अत्यधिक गर्म होना और चार्जिंग के दौरान की गई लापरवाही जैसे कारण हो सकते हैं। ऐसे हादसों का खतरा कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है।

मोबाइल को हमेशा कंपनी के मूल चार्जर या प्रमाणित और भरोसेमंद चार्जर से ही चार्ज करें। सस्ते, नकली या बिना प्रमाणित चार्जर के इस्तेमाल से बचें। बिस्तर या तकिए पर रखकर चार्ज न करें: चार्जिंग के दौरान फोन गर्म हो सकता है। उसे बिस्तर, कंबल या तकिए पर रखने से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। फोन को किसी सख्त और सपाट जगह पर रखकर चार्ज करें। फोन ज्यादा गर्म हो तो सावधान रहें: चार्जिंग के दौरान फोन असामान्य रूप से गर्म हो रहा हो, तो उसे चार्जिंग से हटाकर ठंडा होने दें। जरूरत पड़ने पर जांच कराएं। मोटा आवरण गर्मी बाहर निकलने में बाधा बन रहा हो, तो चार्जिंग के समय उसे हटा दें।

सिक्किम के सोरेंग में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित

- **केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने 375 लाख रुपये की मत्स्य परियोजनाओं का किया उद्घाटन**
- **पूर्वोत्तर में जैविक प्रमाणीकरण की मानक संचालन प्रक्रिया शुरू**



नईदुनिया ब्यूरो, सोरेंगः सिक्किम के सोरेंग जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को पूर्वोत्तर में मत्स्य पालन के जैविक प्रमाणीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सिक्किम में 375 लाख रुपये की मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

केंद्रीय मंत्री ने मंगन जिले के दौरे के दौरान मत्स्य पालन विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सिक्किम सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि मंत्री पूरन कुमार गुरुंग, मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों और मछली किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। दो सहकारी समितियों के 15 किसानों को मछली चारा वितरित किया गया। उन्होंने मत्स्य पालन, सजावटी मछलियों और मूल्यवर्धित उत्पादों के साथ स्थानीय जैविक सब्जियों तथा डेयरी उत्पादों के प्रदर्शन का भी निरीक्षण किया।

375 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उद्घाटित परियोजनाओं में मत्स्य पालन की महत्वपूर्ण सुविधाएं शामिल हैं। इनमें मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, चारा मिल, शीत भंडारण सुविधाएं तथा जैव प्रवाह और पुनर्चक्रण आधारित मत्स्य पालन प्रणालियां शामिल हैं। मछली किसानों को संस्थागत ऋण की सुविधा के लिए किसान ऋण कार्ड वितरित किए गए। मुख्यमंत्री मत्स्य उत्थान योजना के तहत पांच किसानों को वित्तीय सहायता के चेक भी प्रदान किए गए।

जैविक उत्पादन और बाजार विस्तार पर जोर

सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को एकीकृत करने के लिए समूह आधारित विकास व्यवस्था अपनाई है। इसके तहत देशभर में 34 मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण समूह अधिसूचित किए गए हैं। सिक्किम और मेघालय में जैविक मत्स्य पालन समूह भी शामिल हैं। सोरेंग का जैविक मत्स्य पालन समूह हानिकारक रसायनों, प्रतिजैविक दवाओं और कीटनाशकों के बिना मछली पालन को बढ़ावा देगा। इसमें अमूर कार्प, भारतीय प्रमुख कार्प और ट्राउट के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा पर एक और प्राथमिकी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा की मुश्किलें एक नए मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बढ़ गई हैं। मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने में उनके खिलाफ वर्ष 2019 के भिवंडी जमीन सौदे और दक्षिण मुंबई के एक फ्लैट की खरीद-बिक्री से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि इस सौदे के जरिए उसे 6.67 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।

- **भिवंडी जमीन सौदे और दक्षिण मुंबई के फ्लैट की खरीद-बिक्री में कंपनी को 6.67 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप**

कंपनी की शिकायत के मुताबिक, राजेंद्र लोढ़ा ने अपने पद और अधिकारों का कथित दुरुपयोग करते हुए भिवंडी की जमीन से जुड़े सौदे को दक्षिण मुंबई स्थित कंपनी के एक फ्लैट की बिक्री से जोड़ दिया। शिकायत में कहा गया है कि फ्लैट की शुरुआती कीमत 6.86 करोड़ रुपये थी, लेकिन कथित तौर पर 1.5 करोड़ रुपये की छूट देकर इसे 5.36 करोड़ रुपये में बेचने की व्यवस्था की गई।

आरोप है कि सैकवीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एलएलपी के निदेशकों ने फ्लैट खरीदने में रुचि दिखाई थी और कंपनी को 36 लाख रुपये का भुगतान भी किया। इसके बाद भिवंडी जमीन सौदे में दलाली और अन्य सेवाओं के नाम पर पांच करोड़ रुपये का भुगतान फ्लैट की शेष कीमत में समायोजित करने का निर्देश दिया गया। शिकायत के अनुसार, इसी व्यवस्था के तहत दस्तावेज तैयार कर फ्लैट सैकवीर बिल्डर्स के नाम आवंटित किया गया।

स्पेशल खबर कोयला उठाव में 25.54 और अधिभार हटाने में 36.10 प्रतिशत की वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने में महत्वपूर्ण योगदान...

सात माह में कोयला उत्पादन 32.96 मिलियन टन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में शानदार परिचालन प्रदर्शन के साथ कंपनी की प्रमुख विकास इंजन बनकर उभरी है। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान यह कोल इंडिया की एकमात्र सहायक कंपनी रही, जिसने कोयला उत्पादन, उठाव और अधिभार हटाने के तीनों प्रमुख मानकों में अपने निर्धारित लक्ष्य को पार किया। इस अवधि में कंपनी ने उत्पादन लक्ष्य का 102.47 प्रतिशत, उठाव लक्ष्य का 108.82 प्रतिशत और अधिभार हटाने के लक्ष्य का 104.56 प्रतिशत हासिल किया। कंपनी का अतिरिक्त कोयला उत्पादन 4.53 मिलियन टन रहा, जो इसी अवधि में कोल इंडिया की कुल शुद्ध उत्पादन वृद्धि से भी अधिक है।



कोयला भंडार में 66 प्रतिशत की कमी

कंपनी ने खदानों के मुहाने पर जमा कोयले के भंडार को एक अप्रैल के 13.034 मिलियन टन से घटाकर 31 अक्टूबर तक 4.44 मिलियन टन कर दिया। इस तरह लगभग 8.6 मिलियन टन कोयले का निस्तारण किया गया। रेलवे के साथ बेहतर समन्वय से 31 अक्टूबर तक 6,146 मालगाड़ियों के डिब्बों का उपयोग किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 4,402 था। इसमें 39.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति में 40.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

निगरानी और तकनीक से बढ़ी परिचालन दक्षता

कंपनी ने दैनिक समीक्षा, नियमित बैठकों और वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के माध्यम से खदान स्तर पर परिचालन बाधाओं का समाधान किया। रेलवे, राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय से पर्यावरणीय और वन संबंधी मंजूरियों में भी सहायता मिली।

अक्टूबर में उत्पादन और उठाव में उल्लेखनीय वृद्धि

अक्टूबर 2026 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स का कोयला उत्पादन पिछले वर्ष के इसी महीने के 3.60 मिलियन टन से बढ़कर 5.93 मिलियन टन हो गया। इस तरह उत्पादन में 64.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने मासिक उत्पादन लक्ष्य का 108.60 प्रतिशत हासिल किया। कोयला उठाव भी पिछले वर्ष के 4.44 मिलियन टन से बढ़कर 6.67 मिलियन टन हो गया, जो 50.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी मासिक उठाव लक्ष्य पार करने वाली प्रमुख सहायक कंपनियों में एकमात्र रही। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान कंपनी ने 32.96 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जिसमें 15.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में 41.56 मिलियन टन कोयले का उठाव हुआ, जबकि अधिभार हटाने का आंकड़ा 207.95 मिलियन घन मीटर रहा। इसमें क्रमशः 25.54 और 36.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।